MINISTRY OF COMMUNICATION & INFORMATION TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS
TA-1 Section, Room No.1312,
SANCHAR BHAWAN, 20-ASHOKA ROAD,
NEW DELHI-110001.

No.7-1/2009/TA-1/1684 to 7771

To

All Heads of Pr. CCA/CCA Offices.
DG (NICF), Ghaziabad,
Director (Accounts-II), DOT HQ.

Sub: Advances to Government servants - Rate of interest for purchase of Conveyances.

Enclosed please find the copy of O.M No. 5 (2)-8 (PD)/2013 dated 12th November, 2013 received from Ministry of Finance, New Delhi along with its enclosure on the subject cited above for information and necessary action.

Encl: As above

Copy to: Director (IT), DOT HQ, (along with copy of above O.M. for uploading the order in the DOT website.)
OFFICE MEMORANDUM

Subject: Advances to Government servants — Rate of interest for purchase of conveyances during 2013-2014.

The undersigned is directed to state that the rates of interest for advances sanctioned to the Government servants for purchase of conveyances during 2013-2014 i.e. from 1st April, 2013 to 31st March, 2014 are revised as under:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Rate of interest per annum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(i) Advance for purchase of conveyance other than motor car (viz. motor cycle, scooter etc.)</td>
</tr>
<tr>
<td>(ii) Advance for purchase of motor car</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(A.K. Bhatnager)
Under Secretary (Budget)

All Ministries/Departments of the Government of India with spare copies for IFA, Controller of Accounts and Pay and Accounts Offices.
2. Finance Secretaries of UTs without legislature.

Copy forwarded to:
1. C&AG of India, New Delhi.
4. All AGs and Director of Accounts.
5. Supreme Court of India.
6. UPSC, New Delhi.

(A.K. Bhatnager)
Under Secretary (Budget)
नवी दिल्ली, विनांक 12 नवंबर 2013

कार्यालय झापन

विषय:- सरकारी कर्मचारियों को लिए जाने वाले अधिनियम - 2013-2014 के दौरान बाहर खरीदने के लिए व्याज की दर

अधिष्ठात्रीय को यह कहना चाहिए कि वर्ष 2013-2014 के दौरान अर्थात पहली अंडर, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि में दानों की खरीद के लिए सरकारी कर्मचारियों को स्वीकृत किए जाने वाले अधिनियम के लिए व्याज की दर में संीदन नियमनुसार हैं-

व्याज की वार्षिक दर

(i) मोटर-कार को छेड़कर अन्य वाहन खरीदने के लिए अधिनि (अर्थात मोटर-साइकिल, स्टूटर आदि) 9 प्रतिशत
(ii) मोटर-कार खरीदने के लिए अधिनि 11.5 प्रतिशत

सेवा में
1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सलाहकारों, लेखा नियंत्रकों और वेतन पुनः लेखा कार्यालयों के लिए अतिरिक्त प्रतिलिपियों सहित।
2. विभा विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सहित।

प्रतिलिपि श्रेणी:-
1. भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षा, नई दिल्ली।
2. तेलंग नागपुर, नई दिल्ली।
3. खाल लेखा महानियत्रक, नई दिल्ली।
4. सभी महालेखा कार्यालयों और लेखा नियंत्रक विभा।
5. भारत का विदेश न्यायालय।
6. संघ लेखा आयोग, नई दिल्ली।

(ए.के. भटनागर) अगर सचिव (कऱ्ढट)

प्रतिनिधि नियंत्रक सरकार विभाग (फाउनिक) एन.एच.एस.सी-136141103
RESOLUTION

It is announced for general information that during the year 2014-2015, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 8.7% (Eight point seven per cent) per annum. This rate will be in force during the financial year beginning on 1.4.2014. The funds concerned are:

1. The General Provident Fund (Central Services).
2. The Contributory Provident Fund (India).
3. The All India Services Provident Fund.
4. The State Railway Provident Fund.
5. The General Provident Fund (Defence Services).
6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
7. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
8. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.
9. The Defence Services Officers Provident Fund.

2. Ordered that the Resolution be published in Gazette of India.

(Peevyush Kumar)  
Director (Budget)

To,

The Manager, (Technical Branch)  
Government of India Press, Faridabad.

F.No.5(1)-B(PD)/2014  
Copy forwarded to all Ministries/Departments of Government of India, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Union Public Service Commission, Supreme Court, Election Commission and Planning Commission.

Copy also forwarded to:

1. Comptroller & Auditor General of India and all offices under his control.
2. Chairman, Pension Fund Regulatory and Development Authority.
3. Controller General of Accounts (10 copies).
4. Ministry of Personnel Public Grievances and Pension (Pension Unit/All India Services Division).
5. Financial Advisers of Ministries/Departments (6 copies).
6. Chief Controllers of Accounts/Controllers of Accounts of Ministries/Departments.
8. Finance Secretaries of all State Governments and Union Territories.
10. Secretary Staff Side, National Council of JCM.
11. All Members, Staff Side, National Council of JCM.

(A.K. Bhatnagar)  
Under Secretary (Budget)

Printed by Ministry of Finance (Press)-4200022014
संकल्प

आम जानकारी के लिए यह प्रोक्ट प्रकाशित किया जाता है कि वर्ष 2014-2015 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभियंताओं की कुल जमा रकमें पर दिए जाने वाले खाते की दर 8.7% (आठ पाइट सात प्रतिशत) प्रतिवर्ष रहेगी। यह दर 1.4.2014 से आरम्भ होने वाले तितिया वर्ष के दौरान लागू रहेगी। संबंधित निधियाँ निम्नलिखित हैं:-

1. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवायें)
2. अंशदाती भविष्य निधि (सरकार)।
3. अधिकृत भारतीय सेवा भविष्य निधि।
4. सरकार रेलवे भविष्य निधि।
5. सामान्य भविष्य निधि (आधा सेवाएं)।
6. भारतीय आर्थिक विभाग भविष्य निधि।
7. भारतीय आयुक्त कार्यालय कामसूची बंधन निधि।
8. भारतीय नौसेना गोदाम कामसूची बंधन निधि।
9. आधा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
10. सरकार सेवा कार्यालय भविष्य निधि।

2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सरकार के संपत्त वर्ष में प्रकाशित किया जाए।

(पीयुष कुमार)
निदेशक (बजट)

सेवा में,
अबेंक, (तकनीकी शाखा)
भारत संस्कृति मुद्रालय,
वरीदावरा।

वित्त मंत्रालय (मुद्रालय) ज्ञात मुद्रौत-205032014
अधिसूचना
एक.संख्या 5(3)-भी (प.डी.)/2013
भारत सरकार
विभ. मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

नवी निर्देश, निर्देश 12 नवंबर 2013

कार्यालयी आदेश

विषय: कार्यालयी आदेश द्वारा जिले जनसंख्या और अभियोग - बीजल जो दे से और आर्थिक/ अर्थ कार्य नियमन तथा यथाशक्ति।

उपर्युक्त निर्देश पर इस मामले के निर्देश 7 जनवरी, 2013 के कार्यालयी आदेश एक.संख्या 5(3)-भी (प.डी.)/2012 के संरक्षण में।

2. उपर्युक्त कार्यालयी आदेश में निर्धारित बाजार वर्ग की संक्षेपण की गई है।

3. कार्यालयी आदेश में जिले जनसंख्या की आधि और आर्थिक/ अर्थ कार्य नियमन तथा यथाशक्ति से संबंधित दे निहित धाराओं को दे गई है।

4. जिले जनसंख्या की आधि और आर्थिक/ अर्थ कार्य नियमन तथा यथाशक्ति,

1. राज्य सरकार के (i) अभियोग ऑफिसर (एक वर्ग के अंतर स्पष्ट विधि द्वारा नियुक्त) और (ii) आयुक्त राज्य सरकार के अधीन

2. संघ राज्य रक्षा के स्तर (बिना नीति नियम) के (i) अभियोग अधिकारी और (ii) आयुक्त राज्य सरकार के अधीन

3. भारतीय सेवा के अधीन नीति नियमित व आयुक्त राज्य सरकार के अधीन

4. भारतीय सेवा के नियुक्ती का अधीन,

(i) विभाग, विभागीय नित नियम (भ.प्र.पी.) के लिये अभियोग नियमित
(ii) संघर्ष पूर्व और संघर्ष विशेष बैंक (नागरी) और संघर्ष पूर्व दल के संघर्ष नियम (संघर्ष नियम)
(iii) भारतीय सेवा, संघर्ष विभाग (प्रायोजन) और दल निवास नियम (प्रायोजन)
(iv) अन्य अन्य

क्रम एवं प्रति 1(1) और 2 (ii) के तहत 'अभियोग' के लिये निर्धारित बाजार और बैंक शाखाओं के लिये विधि द्वारा उपर्युक्त बैंक और विधि द्वारा उपर्युक्त बैंक के लिए अभियोग नियमित के अंतर स्पष्ट विधि द्वारा नियुक्त और आयुक्त राज्य सरकार के अंतर स्पष्ट विधि द्वारा नियुक्त.

3. केवल अभियोग राज्य सरकार के अंतर स्पष्ट विधि द्वारा नियुक्त और आयुक्त राज्य सरकार के अंतर स्पष्ट विधि द्वारा नियुक्त और आयुक्त राज्य सरकार के अंतर स्पष्ट विधि द्वारा नियुक्त.

4. उपर्युक्त निर्धारित बाजार दे से अभियोग और आयुक्त राज्य सरकार के अंतर स्पष्ट विधि द्वारा नियुक्त और आयुक्त राज्य सरकार के अंतर स्पष्ट विधि द्वारा नियुक्त.

| Category of borrower | प्रति वर्ष बाजार की हैरानी दर का प्रति वर्ष राज्य की हैरानी की प्रतिशत दर पर सर्वे में | अभियोग राज्य सरकार के अंतर स्पष्ट विधि द्वारा नियुक्त और आयुक्त राज्य सरकार के अंतर स्पष्ट विधि द्वारा नियुक्त.
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. State Governments: (i) Ways and Means Advances (Recoverable within the year)</td>
<td>8.25</td>
<td>8.25</td>
</tr>
<tr>
<td>(ii) Other Loans</td>
<td>8.75</td>
<td>8.75</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Union Territory Governments (with Legislature): (i) Loans upto 1 year</td>
<td>8.25</td>
<td>8.25</td>
</tr>
<tr>
<td>(ii) Other Loans</td>
<td>8.75</td>
<td>8.75</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Industrial and Commercial Undertakings in the Public Sector and Cooperatives. (i) Investment loans</td>
<td>11.50</td>
<td>11.50</td>
</tr>
<tr>
<td>(ii) Working Capital loans and loans to meet Cash losses</td>
<td>13.50</td>
<td>13.50</td>
</tr>
<tr>
<td>(iii) Loans for implementation of VRS in sick PSUs</td>
<td>11.50</td>
<td>11.50</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Financial institutions in the Public Sector, Port Trusts, KVIC, NHAI, Municipal Corporation of Delhi, Commodity Boards, Social Service Institutions, Individuals, etc. (i) Rural Electrification Corporation: (a) For Minimum Needs Programme (M.N.P.)</td>
<td>10.00</td>
<td>10.00</td>
</tr>
<tr>
<td>(b) Others</td>
<td>10.00</td>
<td>10.00</td>
</tr>
<tr>
<td>(ii) National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) and National Cooperative Development Corporation (NCDC)</td>
<td>10.00</td>
<td>10.00</td>
</tr>
<tr>
<td>(iii) National Highways Authority of India (NHAI) and Port Trusts</td>
<td>10.00</td>
<td>10.00</td>
</tr>
<tr>
<td>(iv) Others</td>
<td>11.50</td>
<td>11.50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

The rate of interest prescribed for "Other Loans" under sub-para 1 (ii) and 2 (ii) above is also applicable for Additional Central Assistance (ACA) on the un-disbursed amount of the loan/issues for all disaster Reconstructions and Rehabilitation Programme assisted by World Bank & ADB.

The loans to State Electricity Boards, Damodar Valley Corporation under the scheme for renovation and modernisation of thermal power stations would carry interest at the same rate as applicable to 'Other Loans' to State Governments. Normally, loans should not be given to Private Sector Companies. In exceptional cases where such loans become necessary interest should be 1/2% higher than those prescribed for Public Sector.

3. The terms including interest rate of loans to Foreign Governments may be settled in consultation with Budget Division. Terms for on-lending of funds under externally aided projects should be in accordance with the prescribed pattern. In case, deviation is considered necessary, Budget Division should be consulted.

4. The interest rates prescribed above assume timely repayments and interest payments and hence no further rebate in rates is to be allowed for timely payments.
5. **OTHER TERMS AND CONDITIONS**
The instructions issued from time to time have been reviewed and are set out in the following paragraphs for facility of reference.

6. **STATE GOVERNMENTS**
In the case of loans to State Governments, the arrangements for payment of annual instalment of principal and interest will be as under:

(a) **Block loans for State Plan Schemes and other Plan loans for Centrally Sponsored Schemes**: These loans when drawn in instalments, will be consolidated and deemed to have been drawn as on 1st October in each year. The maturity period of the loans sanctioned for State Plans is 20 years, repayments being made in 20 annual equal instalments together with interest on the outstanding balance commencing from the following year, subject to consolidation under the award of Twelfth Finance Commission (TFC).

However, fifty per cent of these loans will enjoy a five year initial grace period, after which repayments of these loans will be effected in 15 annual equal instalments. The amounts annually payable (by way of principal and interest) would be recovered in 10 equal monthly instalments commencing 15th June, subject to debt waiver under the award of TFC.

(b) **Other Loans**: The terms of repayment of these loans will be as laid down from time to time.

7. **PUBLIC SECTOR PROJECTS**

(A) **For new installations or expansion of existing institutions**:

(a) The terms and conditions of loans should be fixed with reference to the financial picture presented in the approved Project Report. (Once the pattern is settled, there should be no change except with the specific concurrence of this Department for reasons to be stated in writing).

(b) **The capital requirements of a project should include adequate provisions for interest payment on borrowings during the period of construction (as specified in the Project Report)**. This interest on loans due during the period of construction will be allowed to be capitalised to the extent of the provisions made for this purpose in the approved Project Report. In other words, while interest on loans advanced to an undertaking during the period of construction will be notionally recovered by allowing its capitalisation, the payment of interest should effectively commence after the construction period is over.

(c) **The repayment of principal should ordinarily commence one year after the project commences production**, the number of instalments being determined with reference to the financial projections and repaying capacity specified in the Project Report. Requests for further moratorium should be considered only in exceptional cases where the Project Report has specified any special circumstances that may necessitate a longer period of moratorium and has indicated clearly what staggering of repayment would be needed over the necessary break period. The period of loans sanctioned against capitalised interest during the period of construction may also be on the same terms and conditions as are applicable to loans provided for financing the project costs.

(d) **A suitable period of moratorium subject to a maximum of five years from the date of drawal of the loans may be allowed for the repayment of instalments of principal, having regard to the nature of the project, the stage of construction etc.** The period of moratorium should not, however, extend in any case, beyond two years from the date of project going into production, or in the case of programmes of expansion, beyond two years from the date of expanded project coming into operation.

(B) **For meeting working capital requirements**:

The undertakings are expected to obtain their cash credit requirements from the State Bank of India/Nationalised Banks by hypothecating their current assets (such as stock of stores, raw materials, finished goods, work in progress, etc.) and where the entire working capital requirements cannot be raised in this manner by seeking a guarantee from Government. Accordingly, requests from Public Sector Undertakings for funds for meeting working capital requirements should be considered only to the extent the same cannot be had from the State Bank of India/Nationalised Banks.
8. GENERAL

REPAYMENT PERIOD

(A) (i) The period for repayment of loans for all parties other than State Governments should be fixed with due regard to the purpose for which they are advanced and it should be restricted to the minimum possible. Normally, no loan should be granted for a period exceeding 10 years. Where a longer period for repayment is sought, prior concurrence of the Budget Division in this Department will be necessary for fixing the period.

(ii) The repayment of a loan should normally commence from the first anniversary date of its drawal or on expiry of the period of moratorium, as the case may be. The recovery should ordinarily be effected in annual equal instalments of principal.

(iii) The period of repayment of working capital loans should preferably be restricted to two or three years. In no case, however, the period of these loans should exceed 5 years.

(B) Moratorium: Subject to exceptions made in respect of public sector projects, a suitable period of moratorium towards repayment might be agreed to in individual cases having regard to the project for which the loans are to be utilised. However, no moratorium should ordinarily be allowed in respect of interest payment on loans. Ministries/Departments may with the approval of their Financial Advisers allow moratorium on repayment of principal wherever considered necessary up to a maximum period of 2 years.

(C) (i) Repayment before due date: Any instalment paid before its due date may be taken entirely towards the principal provided it is accompanied by payment towards interest due up to date of actual payment of instalment; if not, the amount of the instalment will first be adjusted towards the interest due for the preceding and current periods and the balance, if any, will alone be applied towards the principal. Where the payment of the instalment is in advance of the due date by 14 days or less, interest for the full period (half year or full year as the case may be) will be payable. If any State Government repays an instalment of a loan which is consolidated as on 1st October, in advance of the due date by more than 14 days the interest will be payable with reference to the actual date of repayment.

(ii) Pre-payment premium: Prepayment premium of 0.25% on the loans with residual maturity of less than 10 years and 0.50% for the loans with residual maturity of 10 years and above, shall be charged. The provision does not apply to the loans to State/UT Governments.

(D) Penalty Clause: The loan sanctions/arrangements should invariably include a penalty clause providing for levy of a penal rate of interest in default of payment in respect of instalments of principal and/or interest. The penal rate of interest should not be less than 2.50% above the normal rate of interest at which a loan is sanctioned.

(E) Defaults in repayment/interest payment:

(i) In the event of a default in repayment of loan/interest payment, the recovery of interest at penal rate may not be waived unless there are special reasons justifying so. However, a decision in this regard will be taken by the Ministry of Finance (Budget Division) on the advice of Financial Adviser. Even in such cases, a minimum of 0.25% should be recovered from the defaulting party as penalty.

(ii) The penalty rate of interest is chargeable on the overdue instalments of principal and/or interest from the due date of their payment to the date proceeding the date of actual payment.

(iii) Whenever a fresh loan is to be sanctioned to a borrower who has earlier defaulted, the loan sanctioning authority must consider the question of recovery of defaulted dues. All releases to Public Sector Undertakings against budgeted outlays should be made only after adjusting the defaults, if any, pertaining to repayment of loans and interest. If for special and exceptional reasons such adjustments are not possible, specific orders of Secretary (Expenditure) should be obtained through Budget Division, before release of fresh loans, in relaxation of extant orders, in conformity with this Division circular No.F.2 (198)-B(SD)/91, dated 15.10.1991.
(v) अन्य स्थानों में भूमि के लिए अनुदानः  
(ii) अन्य स्थानों में धारा 8 के तहत जब भूमि को दान के लिए प्राप्त करने वाले नगर प्रशासनीय कार्यालयों ने उपरोक्त नियमों की विस्तारित परिभाषा दी है।

(vi) अन्य स्थानों में भूमि के लिए अनुदानः  
(ii) अन्य स्थानों में धारा 8 के तहत जब भूमि को दान के लिए प्राप्त करने वाले नगर प्रशासनीय कार्यालयों ने उपरोक्त नियमों की विस्तारित परिभाषा दी है।

(G) Loans sanctioned at concessional rates:  
(i) In cases where loans are, to be sanctioned at a concessional rate, the instructions contained in Rule 223 (1) of G.F.R. 2005 have to be observed. In such cases, payment of subsidy (to cover the concession viz. difference between normal rate and concessional rate) should be made conditional upon prompt repayment of any default in repayment, interest at rates prescribed by Government from time to time will be chargeable on the loans.

(iii) Similarly, in the case of interest free loans to departmental canteens where subsidy is also provided to meet running expenses, the sanction letter should stipulate that in the event of any default in repayment, the defaulted dues would be recovered out of the subsidy payable.

(H) Miscellaneous: A standard form prescribed for issue of loan sanctions (Appendix I) should ordinarily be followed.

(i) The date of drawal of a loan by the borrower will be date on which he received cash, cheque or bank draft from the Drawing and Disbursing Officer. It should be ensured that the time lag between the date of obtaining the cash/cheque/bank draft and its disbursment/delivery/despatch to the payee is reduced to the minimum. Where the cheque or bank draft is sent through post, the date of posting should be treated as the date of disbursement of the loan. The Drawing and Disbursing Officer should invariably intimate the date of
payment to his Accounts Office to enable the latter to make a suitable note in his records.

(ii) In the case of loans sanctioned to parties other than State and Union Territory Governments and Government Servants, the borrower should tender the amounts due on or before the due date, at the New Delhi Office/Main Office of the public sector bank accredited to the Ministry/Department which sanctions the loan, in cash or by cheque or draft drawn on any scheduled bank in Delhi/New Delhi in favour of the said PSB Branch. The payment should be accompanied by a memorandum or challan in duplicate indicating (a) name of the loan sanctioning Ministry/Department; (b) No. and date of the loan sanction letter and the loan amount sanctioned; (c) amount due for payment separately for interest and principal and the (head(s) of account to which the dues are to be credited in the Government Accounts; and (d) due date of payment. The borrower should be asked to tender separate cheques/drafts and challans for payment of principal and interest.

Outstation loanees are required to arrange the dues through their bank ensuring that the memorandum/challan and the cheque/draft reaches the aforesaid PSB Branch in New Delhi by the due date.

(iii) Ministries/Departments are required to keep close watch on timely repayments of loans advanced by them and recovery of interest thereon. Rule 220 (1) (viii) of G.F.R. 2005 provides for a notice to be given to the borrowers a month in advance of the due date of payment of instalment of the principal and/or interest thereon. Such notices may be sent in the form given in Appendix II. The borrower should not however be given any advantage in the event of non-receipt of such a notice.

Repayments/interest payments due from the loanees should also be reviewed at least quarterly, and where any default has occurred, a fresh notice should be served on the borrower to arrange payment with penal/higher rate of interest in the form set out in Appendix III.

(iv) Individual cases relating to terms and conditions of loans need not be referred to the Department of Economic Affairs (Budget Division) unless it is proposed to deviate from those laid down in this Office Memorandum.

(Peevyash Kumar)
Director (Budget)
Tel. No. 23092744

To
1. All Ministries, their Financial Advisers and Controllers of Accounts.
2. Finance Secretaries of all States and Union Territory Governments and Administrations.
3. Comptroller and Auditor General of India (10 copies).
5. All Accountants General and Directors of Audit.
6. Reserve Bank of India, Bombay (10 copies).
परिस्थिति-पत्र का फायदा

सेवा में,

(रचना और संबंधित क्षेत्रों की सरकारों के गमन में निम्नलिखित को संबंधित किया जाए)

i) मुख्य सेवा नियंत्रक/संबंधित सेवा नियंत्रक

ii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शासन के प्राथमिक विभाग का सचिव

(अन्य गमनों में निम्नलिखित को संबंधित किया जाए)

i) आपको

ii) _________________ नंबर/विभाग का सेवा नियंत्रक

पुराना

(आदेश) में (आदेश) में

पुराना के संबंध में वर्तमान की स्थिति प्रबंधन करने का निर्देश हुआ है।

2. अलावा यहाँ इस पट्टी के अनुसार में दिया गया है।

3. (सर्वसाधारण यह है कि वे बाइक नियंत्रकों के प्राप्तवय प्राप्त करने पर अन्य स्वीकृत किया जाता है क्योंकि जो लोग विशेष किनारे, 2005 के नियम 220 (स) और 225 जे की गई है)

4. यह स्वीकृतरूप से विशेष विभाग की विभिन्न सहमति से निर्धारित नियंत्रकों/नियंत्रकों के अधिकार प्राप्त करने की गई है और अन्य प्राप्त कर की दर तथा उसकी वापसी आदेश की अवधि उनके द्वारा जारी किया गया वार्षिक वित्तीय के अनुसार निर्धारित की गई है।

भद्रेष्ट,

( )

संधिया

( )

संबंधित गृहेश्चारक की प्रति प्रेषित (केन्द्र राज्य और संयुक्त राज्य क्षेत्रों की सरकारों के गमन में)

( )

गृहेश्चारक/विभाग

( )

के प्रयास संधिया

( )

को अनुरोध

केंद्रीय सरकार द्वारा आरोप और अनुमान

1. आरोपकार का नाम

2. मंदिर की गई शिक्षा (आदेशों और संबंधित क्षेत्रों की सरकारों के गमन में)

3. मंदिरों की वैश्विक स्थिति

4. आरोप का प्रभाव

5. नकल प्रभाव देखा आयोग संस्थान से

6. आयोग/आयोगी-विभाग (आयोगों के नामों में आयोगों की स्थिति)

7. आयोग और उस सीरीज के अन्य अनुदान स्वीकृति देखा जाना जाएगी

8. वित्तीय वर्ष में आरोपकार को मंदिर की गई आरोप की प्राप्ती होगी

9. आरोप की आवश्यकता

FORM OF SANCTION LETTER

To

(In case of State and Union Territory Governments to be addressed to)

i) Chief Controller of Accounts/Controller of Accounts concerned.

ii) Secretary of the Administrative Department of the State/UT Government.

(In other cases to be addressed to)

i) The borrower

ii) Controller of Accounts of the Ministry/Department of _________________

Subject:-

Sir,

I am directed to convey the sanction of the President to the payment of loan of Rs. _______________ Rupees _______________ (in figures) to _______________ (in words).

2. The essential details are given in the annexure to this letter.

3. (Conditions on fulfilment of which loan is to be sanctioned e.g. those given in Rules 220 (3) and 225 of G.F.R. 2005 to be inserted, if necessary).

4. This sanction has been accorded in accordance with the rules/principles laid down with the previous consent of the Ministry of Finance and that the rate of interest on the loan and period of repayment thereof have been fixed in accordance with the existing instructions issued by them.

Yours faithfully,

( )

No. _______________ dated _______________

Copy to the Accountant General concerned (In the case of States and Union Territory Governments only).

Annexure to the Ministry/Department of _______________

Dated _______________

LOANS AND ADVANCES BY CENTRAL GOVERNMENT

1. Name of the Borrower

2. Amount sanctioned (in figures & words)

Rs. _______________ (in figures)

Rupees _______________ (in words)

3. Sanction valid upto

4. The purpose of loan

5. Payable in cash or by adjustment


7. Grant & Sub-head under which amount sanctioned is debitable

8. Progressive amount of loan sanctioned to the borrower to date in the financial year

9. Period of loan
10. वापसी अदायभीत के संबंध में

स्वीकार की अवधि यदि कोई है ______________

11. तारीख और वर्तमान जिससे

वापसी-अदायभीत शुरु होनी है ______________

12. वापसी-अदायभीत का तरीका

13. वापसी:

(i) राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों और सरकारी क्षेत्रों के

उद्योगों को क्रय की जाति में:

(a) साधारण पर

(b) वापसी अदायभीत/प्राप्त

की अदायभीती ने देने

(c) भाज्य की बूझी का

का तरीका

(ii) राज्य सरकारों, संघ राज्य

क्षेत्रों की सरकारों और

सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों

के अदायभीत की जाति में

(iii) अदायभीत का तरीका

संख्या

लेखा निवंत्रक का कार्यस्थल

मंत्रालय/भवन

नई दिल्ली, दिनांक ______________

सेवा मे

विवेक- अदायभीत की अदायभीत और उस पर भाज्य की अदायभीती।

प्रिय महंगा,

मंत्रालय/भवन के

दिनांक ______________ पर संख्या प्राप्त करने पर आपके

मंधार सिद्ध किया गया

रूपांतरण के अदायभीत एवं

संघर्षों के अदायभीत की जिस की/अदायभीत के रूप में जिसका

दिनांक ______________ के देख होगी।

(i) वापसी अदायभीत

रूपांतरण

(संबंध एवं अंकों में)

(ii) भाज्य

रूपांतरण

(संबंध एवं अंकों में)

2. कुछ दिन लड़त काम अदायभीत करने की व्यवस्था की जाती।

यह उलझनी नहीं है कि भाज्य की दाताओं का विवेक यह सामना करेगा है कि

अदायभीत का सामना का की दृष्टि जाएगी, अनुसार आक से अदायभीत के

अनुसार जानकारी द्वारा जाने।

3. नई दिल्ली क्षेत्रों की निबंधन दाताओं का अनुसार लिए गए

पर

(संयोजन नर्तका नर्तका ब्यूरो कर्मचारी बैंक (री.एस.बी.)

मंदिर में नकदी

की मंदिर/निवंत्रण से संबंधित हो)

के रूप में अदायभीत का नुक्सान द्वारा निश्चित किया भी अनुसार अदायभीत

क्षेत्रों के नाम उपरेक मानकों के क्षेत्र की नीति दास्तान का रूप में आवश्यक किया गया

हो, अदायभीत की आदेश।

वापसी, एक ज्ञात अदायभीत का सामने देने

के लिए, एक साधारण कार्यक्रम के चलते देने
memorandum or challan, in duplicate, giving the following details:—

(i) Name of the Ministry/Department 
(ii) Name of the Borrower 
(iii) No. and date of the loan sanction letter with the loan amount sanctioned 
(iv) Amount due for payment, separately for interest and repayment 
(v) Due date of payment 
(vi) The head of the account indicated below, to which the amounts will be adjustable in Government accounts, should be included in the challan:—

Head of Account

(i) Instalment of Principal 
(ii) Interest 

4. Separate cheque/draft and challans should be submitted for payment of principal and interest.

5. For outstation loanees, payment of dues together with memorandum/challan is to be arranged through their bank to the aforesaid PSB branch in New Delhi by the due date.

Yours faithfully,

Accounts Officer

---

IMPRESSIVE NOTICE

No. 
Office of the Controller of Accounts 
Ministry/Department 

To

Subject:— Repayment of loan and payment of interest thereon.

Dear Sir,

I am to state that the payment of Rs. _______ and Rs. _______ (as detailed below) representing principal and interest respectively, which fell due on _______ in respect of loans mentioned thereagainst, has not so far been arranged by you.

Loan sanction No. & Date

(i) Principal 
(ii) Interest

2. Please arrange to deposit the aforesaid amount to the account of the Government of India within 10 days of the issue of this letter, failing which other measures would be initiated.

3. In case the payment in question has already been made to the Government, particulars of the cheque/demand draft and the date of deposit at the _______ (Name of the public sector bank branch) may be indicated immediately.

Yours faithfully,

Accounts Officer

---

Registrar A.D. 
APPENDIX-III